



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 8, 1990/फाल्गुन 17, 1911
No. 61 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 8, 1990/PHALGUNA 17 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

न्यू बैंक आफ इंडिया
(वित्तिक विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1990

संख्या 5009.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और
अंतरण अधिनियम—1980 (1980 का 40) की धारा-19 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू बैंक आफ इंडिया के निवेशक
मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार
का पूर्वसंकेति से एतद्वारा न्यू बैंक आफ इंडिया अधिवारी कर्मचारी
विनियम-1982 में निम्नलिखित और संशोधन कराया है।

2 (i) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—यह विनियम न्यू बैंक आफ
इंडिया (अधिवारी) सेवा संशोधन विनियम 1990 कहें जाएंगे।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. न्यू बैंक आफ इंडिया (अधिवारी) सेवा विनियम 1982 में
निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे।

(क) विनियम 3 में संशोधन

उप विनियम 3 (क) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित
किया जाए:

“3 (क) “वेतन” से एतिरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन अभिप्रेत है”।
उप विनियम 3(एल) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—
“3(एल) “वेतन” से मूल वेतन और महंगाई भत्ता का योग अभिप्रेत
है।”

(ख) विनियम 4 में संशोधन

उप विनियम 4(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया
जाए:—

“4(1) 1-2-1984 को और इन तारीख से प्रकाशित की
निम्नलिखित 4 ग्रेड होंगी और प्रत्येक ग्रेड के सामने निम्नलिखित वेतनमान
होंगे:—

(क) कार्यस्थ कार्यपालक ग्रेड :

वेतनमान VII रु. 4100-125-4600

वेतनमान VI रु. 3850-125-4350

(ख) वेतनमान V रु. 3375-110-3685-115-3800

वेतनमान IV रु. 2925-105-3450

(ग) मध्यम प्रबंध ग्रेड :

वेतनमान III रु. 2650-100-3250

वेतनमान II रु. 1825-100-2925

(घ) कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड :

वेतनमान I रु. 1175-60-1475-70-1895-ई को-95-2275-100-2675

1-11-1987 को और इस तारीख से प्रत्येक ग्रेड के सामने निम्नलिखित वेतनमान होंगे :—

(क) सीपैम्प कार्यपालक ग्रेड :

वेतनमान VII रु. 6400-150-7000

वेतनमान VI रु. 5950-150-6550

(ख) उपग्रेड प्रबंध ग्रेड :

वेतनमान V रु. 5350-150-5950

वेतनमान IV रु. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(ग) मध्य. प्रबंध ग्रेड :

वेतनमान III रु. 4020-120-4260-130-4910

वेतनमान II रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड :

वेतनमान रु. 2100-120-4020

वर्षों सरकार के विनियम-8 के तहत किए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार उक्त वेतन में फिट किए गए प्रत्येक अधिकारी को, जो नियत तिथि को लागू वेतनमान द्वारा शासित हों, सरकार के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार उपयुक्त निर्धारित वेतनमान में फिट किया जाएगा।

(ग) विनियम-5 में संशोधन

उक्त विनियम-5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए

“5(1) 1-11-87 को और इस तारीख से निम्नलिखित उपखण्डों के अधीन वेतनवृद्धियां प्रदान की जानी चाहिए:—

(क) विनियम 4(1) में उपखणित विभिन्न वेतनमानों में निम्नलिखित वेतनवृद्धि मंजूर प्राधिकारों को मंजूरी के अधीन रहते हुए वार्षिक आधार पर प्रदत्त होगी और उस मास की पहली तारीख को प्रदान की जाएगी जिसमें वह देय होता है।

(ख) वेतनमान-I और वेतनमान-II के अधिकारों पर जो एक वर्ष पश्चात् अपने संबंधित वेतनमानों में उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हैं उन्हें नीचे उल्लिखित (सी.) में दिए गए अनुसार अपने उच्च वेतनमान में प्रतिबंधित वेतन वृद्धि (यों) सहित पुनः वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उन्होंने दस परसेंट पार कर लिया हो।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित ऐसे अधिकारियों सहित, जो मध्यप्रबंध ग्रेड/वेतनमान II और III में उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हैं और वेतनमान II और III जैसी भी स्थिति हो, को अन्तिम अवस्थाओं पर पहुंचने के प्रत्येक 3 वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए प्रतिबंधित वेतनवृद्धियां प्रदान करेंगे, जो वेतनमान-II की अन्तिम अवस्था पर पहुंचने वाले प्रत्येक अधिकारी के लिए रु. 130/- को दो ऐसी वेतनवृद्धियां अधिकतम होगी और वेतनमान III की अन्तिम अवस्था के अधिकारियों के लिए रु. 140 की पूर्ण वेतनवृद्धि होगी।”

नोट:—अपने उच्च वेतनमान में प्रदान ऐसी वेतनवृद्धियां पदोन्नति के बराबर नहीं होंगी। अधिकारी ऐसी वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के पश्चात् भी अपने अन्तिम वेतनमान I

और II, जैसी भी स्थिति हो, के विशेषाधिकार पर लक्ष्मियों रूपों पर शायित्य निर्वहन जारी रखेगा।

5(2) नियत तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित उपसदस्य की परीक्षा के प्रत्येक भाग की उत्तीर्ण करने के लिए वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी

स्पष्टीकरण :—

ऐसे अधिकारी को, जिसने भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित उपसदस्य की परीक्षा के भाग 1 या भाग 2 को नियत तारीख से पूर्व अधिकारी के रूप में उत्तीर्ण किया है, पर्याप्त अतिरिक्त वेतनवृद्धि या वेतनवृद्धियां नियत तारीख से दी जाएगी परन्तु यह तब जबकि उसने कोई वेतनवृद्धि प्राप्त न की हो या उक्त परीक्षा के दोनों भागों को उत्तीर्ण करने के लिए केवल एक वेतनवृद्धि प्राप्त की हो।

2. 1-11-87 को और इस तारीख से ऐसे अधिकारी जो वेतनमान की उच्चतम सीमा तक पहुंच चुके हैं अथवा पहुंचने वाले हैं और सरकारी मार्गदर्शी निर्देशों को देखते हुए यदि कोई ही पदोन्नति के माध्यम से छोड़कर आगे उन्नति प्राप्त करने में असमर्थ हैं, सी ए आई आई की परीक्षा उत्तीर्ण करने की छान में रखते हुए, अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के प्रति व्यवसायिक योग्यता भत्ता प्रदान किया जाएगा :

जिसमें केवल सी ए आई आई की भाग-I पास किया हो:—

(i) एक वर्ष पश्चात् 100 रुपये प्रतिमाह जिसमें से रु. 75 अधिव्ययिता लाभों के लिए रखे जाएंगे

जिसमें सी ए आई आई की दोनों भाग पास किए हों

(i) एक वर्ष पश्चात् रु. 100 प्रतिमाह जिसमें से रु. 75 अधिव्ययिता लाभों के लिए रखे जाएंगे।

(ii) दो वर्ष पश्चात् रु. 250 प्रतिमाह जिसमें से 200 रु. अधिव्ययिता लाभों के लिए रखे जाएंगे

नोट यदि कोई ऐसा अधिकारी जो व्यवसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त कर रहा है और अपने उच्च वेतनमान में पदोन्नत होता है तो ऐसा उच्च वेतनमान में फिटनेट होने पर, वेतनमान में उतलव्य वेतनवृद्धियों तक और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध न हो अथवा वेतनमान में केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध हो सी ए आई आई की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अतिरिक्त वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएगी अधिकारी वेतनवृद्धियों के प्रति व्यवसायिक योग्यता भत्ते के लिए पात्र होगा।”

(ब) विनियम 21 में संशोधन

विनियम 21 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

1-11-1987 को और इस तारीख से महंगाई भत्ते की योजना निम्न प्रकार है:—

(1) महंगाई भत्ता अल्पतम भारतीय औद्योगिक कामगार की संयोजक मध्य सूचकांक सामान्य आधार वर्ष 1960 = 100 के निमाही औसत को 600 अंकों के ऊपर प्रत्येक अंक के बराबर और निम्न पर 4 अंकों के लिए देय होगा।

(i) महंगाई भत्ता निम्नानुसार दरों पर देय होगा :

- (i) वेतन का 0.67 प्रतिशत 1650 रु तक
 (ii) वेतन का 0.55% 1655 रु से अधिक से लेकर रु. 2835 तक
 (iii) वेतन का 0.38 प्रतिशत 2835 रु. से अधिक से लेकर 4020 रु तक
 (iv) वेतन का 0.17 प्रतिशत 4020 रु से अधिक"
 (क) विनियम 22 में संशोधन

"विनियम 22 के उप नियम (1), (2), (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए—

1-1-1987 को और इस तारीख से यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा रियायती अवकाश मोहवा किया जाता है तो उसके वेतनमान के जिसमें उसे फिट किया जाता है, प्रथम वर्ण के वेतन का 6 प्रतिशत अथवा अवकाश के मानक किराया, जो भी कम हो उससे वसूल किया जाएगा।"

विनियम 22(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

"1-11-87 को और इस तारीख से यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा रियायती अवकाश मोहवा नहीं किया जाता तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा:—

अज्ञात कार्य स्थल समूहों से कहीं हो वेतन मकान किराया भत्ता

- (i) सरकार के मारुद्दर्शी निर्देशों वेतन का 14 प्रतिशत परन्तु के अनुसार समय समय पर अधिक से अधिक रु. 375 यथा विनिर्दिष्ट "क" श्रेणी के शहर और समूह "क" के

परियोजना क्षेत्र के केन्द्र

- (ii) क्षेत्र के अन्य स्थल और 'ख' वेतन का 12% परन्तु अधिक से के परियोजना क्षेत्र के केन्द्र अधिक रु 300

- (iii) (i) और (ii) में न दिए गए वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु क्षेत्र II और राज्य राजधानियों एवं अधिक से अधिक रु 50

लघु राज्य क्षेत्रों की राजधानियों

- (iv) क्षेत्र III वेतन का 8 प्रतिशत परन्तु अधिक से अधिक रु 225

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराये का रणोदें प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा रियायती अवकाश के लिए अर्वा किए गए वार्षिक किराए के बराबर जिस वेतनमान में वह कार्यरत है, उस वेतनमान को पहली अवस्था में 6 प्रतिशत से अधिक अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ता का 160 प्रतिशत अधिकतम, मकान किराया भत्ता वेतन होगा

विनियम-22(3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

जहां कोई अधिकारी अपने स्वयं के निवास स्थान में निवास करता है वहां वह उतने आधार पर मकान किराया भत्ता का पात्र होगा जो उपविनियम (2) में उपबर्णित है, मानो वह नीचे दिए गए "क" या "ख" में से उच्चतर के 12 वे मास के बराबर राशि का मासिक किराए के रूप में संदेय कर रहा हो:—

(क)

निम्नलिखित का योग

- (i) निवास स्थानों का बाबत संदेय नगरपालिका कर और
 (ii) निवास स्थान की पूंजी लागत का 12 प्रतिशत जिसके अन्तर्गत भूमि की लागत भी है और यदि

निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उस भूमि की पूंजी लागत का व यानुषंगिक हिसा जो उस निवास स्थान का भाग का भाग है, किन्तु इसके अन्तर्गत विशेष विवरण त्रिमे वतानुगत नहीं है।

(ख)

निवास स्थान के नगरपालिका निर्धारण के लिए लिखा गया वार्षिक किराया मूल्य स्पाटिफिकेशन

(1) इस विनियम के प्रकाशन के मानक किराया से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(क) ऐसे निवास स्थान को दशा में जो बैंक के सम्मिलित है, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संगणित मानक किराया जो सरकार में ऐसी संगणना के लिये प्रचलित है,

(ख) जहां निवास स्थान बैंक के किराये पर लिया है वहां बैंक द्वारा संदेय संबंधित किराया।

(छ) विनियम 23 में संशोधन:

विनियम (23) के उपविनियम 23 (1) (5), (6), (7) और (10) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये। 1-11-87 को और इस तारीख से यदि यह नीचे सारणी के कालम-1 में दिये गये स्थान पर कार्यरत है, उस स्थान के सामने कालम-2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकार भत्ता बशर्ते कि नगर प्रतिकार भत्ता पनजा और मारुद्गाओं के शहरी समूह से अन्यत्र गोवा राज्य के स्थानों जहां 1-11-87 को प्रकाश नहीं किया था वहां 20-8-88 का प्रभावी निधि देय होगा।

सारणी

स्थान	दरें
क्षेत्र-1 के स्थान पर और गोवा राज्य	मूल वेतन का 6-1/2 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रुपये 200/- प्रतिमाह।

उक्त (क) में ना आने वाले 5 लाख मूल वेतन का 4 प्रतिशत परन्तु और उससे अधिक जनसंख्या वाले अधिकतम रुपये 135 /— स्थानों तथा राज्य, राजधानियों एवं चण्डीगढ़, पॉन्डिचेरी और पोर्ट ब्लेयर।

विनियम 23 (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया:—

1-11-87 को और इस तारीख से यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उन परि-लब्धियों को प्राप्त करने का अधिकार वे सकेगा जो उस पद से संलग्न है जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया है। वैकल्पिक रूप से, वह अपने वेतन के प्रतिरिक्त वेतन का 12 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता जो अधिकतम रुपये 700/- होगा और ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकेगा जो वह उस वहां में प्राप्त करता जब उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात किया जाता।

परन्तु यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उतने स्थान पर अवस्थित जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व तैनात था तो वह अपने वेतन के 6 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता जो अधिकतम रुपये 350/- होगा, प्राप्त करेगा।

यदि कोई अधिकारी बैंक के किसी शिक्षण स्थान को संकाय सदस्य के रूप में प्रयोजन बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने वेतन का 6 प्रतिशत को दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते जो अधिकतम रुपये 350 होगा, पाने का पात्र है।

विनियम 23 (6) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

1-11-87 को और इस तारीख से यदि उसके कम से कम 7 दिन की निरन्तर अवधि के लिये या किसी कैलेंडर माह के दौरान कुल सप्त दिन के लिये किसी उच्चतर ग्रेड में किसी पद में स्थानापन्न के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो वह अपने वेतन का 6 प्रतिशत के बराबर जो अधिकतम रुपये 250/- प्रति माह होगा उस अवधि के लिए स्थानापन्न रूप में कार्य किया है स्थानापन्न भत्ता प्राप्त करेगा। स्थानापन्न भत्ता भविष्य विधि के प्रयोजनों के लिये वेतन होगा और अन्य प्रयोजनों के लिये नहीं होगा।

परन्तु यदि कोई अधिकारी मात्र विनियम 6 के अग्रान पदों के प्रवर्गीकरण के पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो वह उस तारीख से एक वर्ष को अवधि के लिये स्थानापन्न भत्ते का पात्र नहीं होगा जिस तारीख को प्रवर्गीकरण का पुनर्विलोकन प्रभाव होता है।

विनियम 23 (7) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:—

1989-90 वित्तीय वर्ष को और इससे आगे यदि वह माह में तैनात है और जहाँ 31 मार्च, और 30 सितम्बर को लेखा बंदी की जाती है वहाँ दोनों लेख दिवसों में प्रत्येक के लिये रुपये 150/- लेखा बंदी भत्ता दिया जायेगा।

विनियम 23 (10) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये:—

1-11-87 को और इस तारीख से यदि वह नौचे की गई सारणी के स्लैम-1 में उल्लिखित स्थान पर सेवागत है तो उसके स्लैम-2 में उस स्थान के सामने उल्लिखित पद पर पर्वत और ईंधन भत्ता:—

सारणी

स्थान	दरें
(1) समुद्र तल से 1000 मीटर वेतन का 5 प्रतिशत जो अधिक से और उस से अधिक ऊँचाई पर अधिक रुपये 130/- प्रतिमाह। किन्तु 1500 मीटर से कम ऊँचाई पर स्थित क्षेत्र तथा बर्फाना कस्बे।	
(2) समुद्र तल से 1500 मीटर वेतन का 6 1/2 प्रतिशत जो और इससे अधिक किन्तु अधिक से अधिक रुपये 160/- 300 मीटर से कम ऊँचाई प्रतिमाह। पर स्थित कार्यालय	
(3) समुद्र तल से 3000 मीटर वेतन का 15 प्रतिशत जो अधिक और इस से अधिक ऊँचाई से अधिक रुपये 600/- प्रति-वाले कार्यालय माह।	

नोट:—(क) ऐसे अधिकारियों को जो कि 750 मीटर से अनाधिक ऊँचाई पर ऐसे कार्यालय पर तैनात है जो कि अधिक ऊँचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए है और जहाँ 1000 मीटर प्रथम इससे अधिक ऊँचाई पर पार किये बिना नहीं पहुँचा जा सकता उसी दर पर पर्वत और ईंधन भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिस दर पर यह 1000 मीटर तथा ऊँचाई वाले क्षेत्रों के लिए है।

(ख) उक्त श्रेणी से इतर किसी भी केन्द्र पर वर्तमान में दिया जा रहा पर्वत एवं ईंधन भत्ता समाप्त कर दिया गया है। 1-11-87 से 30-4-89 के बीच पहले से भत्ता कर दिये गये भत्ते को वसूली नहीं की जायेगी। 1 मई, 1989 से और एन से आगे मात्र पुराने प्रावधानों के अन्तर्गत 30 अप्रैल को स्थितों अनुसार भत्ता किये गये भत्ते की राशि उन अधिकारियों के मामले में संरक्षित की जायेगी जो उक्त विधि की अवधि उमर में पूर्व, उनीचेनमान में उक्त केन्द्र पर तैनात रहे थे।

विनियम 24 में संशोधन:

विनियम 24 के उपविनियम 1 (क), 1 (ख) (1) और 1 (ख) (5) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

(1) प्रत्येक अधिकारी अपनी और अपने कुटुम्ब की आवश्यकताओं के अनुसार उपगत चिकित्सीय व्यय को निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा अर्थात्:—

(क) चिकित्सीय व्यय:

1-11-87 को और इस तारीख से नौचे की गई सारणी के स्लैम-1 में निम्नलिखित वेतन पराम में किसी अधिकारी और उसके कुटुम्ब के चिकित्सीय व्यय को प्रतिपूर्ति स्वयं अधिकारी के हाथ प्रमाण के आधार पर कि उसे ऐसा व्यय उपाय किया है, जिसके समर्थन स्वरूप दवाकृत रकमों के लिए लेखा विवरण दिया जायेगा, सारणी के स्लैम-2 में निम्नलिखित सीमा तक की जा सकेगा:—

सारणी

वेतन	वार्षिक प्रतिपूर्ति की सीमा
रु. 2100/- से रु. 3060/- प्रतिमाह	रु. 600/-
रु. 3061/- प्रतिमाह और इससे ऊपर	रु. 800/-

नोट:—किसी अधिकारी को ऐसी चिकित्सीय सहायता का, जिसका लाभ नहीं उठाया गया है, किसी समय ऊपर उपर्युक्त अधिकतम रकम से अधिक से अधिक तीन गुने तक संक्षिप्त किया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी का "कुटुम्ब" केवल पति/पत्नी, पूर्णवय आश्रित संतान और पूर्णवय आश्रित माता-पिता से मिलकर बनेगा।

(ख) (1) अस्पताल में भर्ती व्यय

(1) 1-4-89 को और इस तारीख से अस्पताल में भर्ती प्रभावों को किसी अधिकारी को दशा में 90 प्रतिशत तक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को दशा में 80 प्रतिशत तक उन मामलों में प्रतिपूर्ति की जायेगी जिनमें अस्पताल में भर्ती किया जाता अग्रक्षित है।

(5) 1-4-89 को और इस तारीख से जहाँ माह में प्राप्त अस्पताल अधिकारियों तथा बैंक का चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाये कि निम्नलिखित कारणों के संवेन में जिनमें अस्पताल में रह कर उपचार कराया जाने की आवश्यकता है, किए गये खर्च को अस्पतालकरण व्यय माना जाएगा और अधिकारियों के मामले में 80% तक उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जायेगी:—

कैंसर, तपेक्षिक, लकवा, बुद्ध-रोग, रसौली, चेचक, म्लूरीसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, गुद की बीमारियाँ।

विनियम 25 में संशोधन:—

विनियम 25 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

1-11-87 को और इस तारीख से कोई भी अधिकारी के रूप में बैंक द्वारा नियुक्त स्थान दिगुजाने का हवाशर नहीं होगा। तथापि बैंक अधिकारी द्वारा अपने वेतनमान जिसमें वह कार्यरत है, को प्रथम अवस्था का 6 प्रतिशत या निम्न स्थान का मानक किगया इनमें से जो भी कम हो, उसका संदाय करने पर नियुक्त स्थान को व्यवस्था कर सकेंगे। बशर्ते कि यदि ऐसे आवाम में बैंक द्वारा अधिकारों को फर्निचर उपबंध कराया जाता है तो उसके वेतनमान को प्रथम अवस्था में उसके वेतन के बड़े प्रतिशत राशि के समतुल्य कटौती की जायेगी। परन्तु उपलब्ध यह है कि जहाँ कहीं ऐसा रिहायशा आवाम बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो बिद्युत, जल, गैस, तथा सफाई के प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

विनियम 34 में संशोधन:

विनियम 34(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

1-1-89 को और इस तारीख से प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक पूरे वर्ष का सेवा के लिए 30 दिन का बीमारी को छुट्टी का पात्र होगा। किन्तु ऐसे छुट्टी सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम 18 माह तक गणित की जायेगी। सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान ऐसा छुट्टी 540 दिन तक संचित की जा सकेगा और बैंक को स्वाधिकार या बैंक के विवेकानुसार उसके द्वारा अपने खर्च पर नाम-निर्दिष्ट व्यक्तिता व्यवसायी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र को पेश किए जाने पर हा की जा सकेंगे।

विनियम 35 में संशोधन:—

विनियम 35 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

1-1-89 को तथा इससे आगे जहाँ अधिकारी ने 24 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया होता है वह 24 वर्ष से ऊपर सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के लिए एक सप्ताह का दर से बीमारी का अतिरिक्त छुट्टी का पात्र होगा। किन्तु बीमारी का यह अतिरिक्त छुट्टी अधिकतम तीन माह तक होगा।

विनियम 41 में संशोधन:

विनियम 41 के उप-विनियम 1 (1), (2), (3), (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:

बोर्ड द्वारा निर्धारित निधि को और इससे आगे; जब कमो कमो अधिकारी से श्रुती पर यात्रा करने की प्रवृत्ति को जाती है तब निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे:—

- (1) कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड में अधिकारी प्रथम श्रेणी रेल अथवा वातानुकूलित यात्रिका द्वारा यात्रा कर सकता है। तथापि वह कार्य को आवासीय अथवा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने अनुमति मिलने पर विमान द्वारा (मितव्ययों श्रेणी) से यात्रा कर सकेगा।
- (2) मध्य प्रबन्ध ग्रेड में अधिकारी प्रथम श्रेणी रेल अथवा वातानुकूलित यात्रिका द्वारा यात्रा कर सकता है। तथापि यदि यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो तो वह विमान द्वारा मितव्ययों श्रेणी से यात्रा कर सकेगा। तथापि वह छोटी दूरी के लिए भी विमान (मितव्ययों श्रेणी) से यात्रा कर सकेगा, बशर्ते कि कार्य को आवासीय अथवा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो।
- (3) वरिष्ठ प्रबन्ध तथा शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा विमान (मितव्ययों श्रेणी) द्वारा यात्रा कर सकेंगे।

- (4) वरिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड अथवा शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड में अधिकारी ऐसे स्थानों पर कार द्वारा यात्रा कर सकेंगे जो विमान अथवा रेल में न जुड़ा 30 बशर्ते कि यह भी 500 किलोमीटर की दूरी से अधिक न हो। तथापि दो स्थानों के बीच दूरी के प्रमुख हिस्से को विमान अथवा रेल द्वारा ही तय किया जायेगा तथा शेष दूरी सामान्यतया कार द्वारा तय की जायेगी।

विनियम 42 में संशोधन:

विनियम 42 (2) (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

1-1-87 क. और इस तारीख से अन्तरण पर अधिकारी को मासगाड़ी द्वारा अपने स्थान के परिवर्तन के लिए व्यय को निम्नलिखित सीमाओं तक प्रतिपूर्ति की जायेगी:—

वेतन	यदि उसका कटू- स्व है	यदि उसका कटू- स्व नहीं है।
र. 2100/- प्रतिमाह से र. 3000 कि. प्रा. 3060/- प्रतिमाह तक	1000 कि. प्रा.	1000 कि. प्रा.
र. 3061/- प्रतिमाह और इससे पुरा पैगत अधिक	2000 कि. प्रा.	2000 कि. प्रा.

विनियम 45 में संशोधन:

विनियम 45 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:

बैंक समय-समय पर, वित्तीय निधि को शामिल करने वाले नियमों के अनुसार वित्तीय निधि में अधिदाय करेगा, परन्तु उसके द्वारा अधिदाय की गई रकम अधिकारी के 1-11-87 से 31-12-88 तक वेतन के 80 प्रतिशत के दम प्रतिशत से अधिक, 1-1-89 से 31-12-89 तक वेतन के 90 प्रतिशत से 10 प्रतिशत से अधिक तथा 1-1-90 से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

विनियम 46 में संशोधन:

विनियम 46 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:

46 (2) किसी अधिकारी को संदेश उद्घरण कारकम सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक मास का वेतन किन्तु अधिक से अधिक 15 माह का वेतन होगा।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरा कर ली है, तो वह उपरान्त के रूप से 30 वर्ष आगे सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए आठ मास के वेतन का दर पर अतिरिक्त रकम के लिए पात्र होगा।

नोट:—यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्ष से आगे सेवाकाल का कोई अंश 6 माह अथवा इससे अधिक है तो उन अंशों के लिए यथानुपातिक आधार पर अंशदान का भुगतान किया जायेगा।

खुशाल सिंह, महावक महप्रबन्धक (कार्यिक)

NEW BANK OF INDIA

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1990

No. 5009.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer

of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of New Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Govt. hereby makes the following regulations further to amend New Bank of India (Officers') Service Regulations, 1982.

2. Short title and commencement : (i) These Regulations may be called New Bank of India (Officers') Service Amendment Regulations, 1990.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the New Bank of India (Officers') Service Regulations, 1982, the following amendments shall be made.

(a) AMENDMENT TO REGULATION 3

Sub Regulation 3(k) shall be submitted by the following :

"3(k) 'pay' means basic pay including stagnation increment"

Sub Regulation 3(1) shall be substituted by the following :

"3(1) 'salary' means the aggregate of the pay and dearness allowance.

(b) AMENDMENT TO REGULATION 4

Sub Regulation 3(1) shall be substituted by the following:

"4(1) On and from 1-2-1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs. 4100-125-4600

Scale VI Rs. 3850-125-4350

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 3575-110-3685-115-3800

Scale IV Rs. 2925-105-3450

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 2650-100-3250

Scale II Rs. 1825-100-2925

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 1175-60-1475-70-1895-EB-95-2275-100-2675

On and from 1-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :

(a) Top Executive Grade :

Scale VII Rs. 6400-150-7000

Scale VI Rs. 5950-150-6550

(b) Senior Management Grade :

Scale V Rs. 5350-150-5950

Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(c) Middle Management Grade :

Scale III Rs. 4020-120-4260-130-4910

Scale II Rs. 3060-120-4260-130-4390

(d) Junior Management Grade :

Scale I Rs. 2100-120-4020

Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government."

(C) AMENDMENT TO REGULATION 5

Regulation 5 shall be substituted by the following:

"5(1) On and from 1-11-1987, the increments shall be granted subject to the following sub-clause :

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4(1) shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 130 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 140 for officers in the last stage of Scale III.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

"5(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of CAIB Examination on or after the appointed date.

EXPLANATIONS

1. In the case of an officer who has passed Part I and/or Part II of CAIB Examination as an officer prior to the appointed date, the additional increment or increments, as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of CAIB Examination.

2. On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIB Examination as under :

Those who have passed : Rs. 100 p.m. after one year, of which Rs. 75 shall rank for superannuation benefits

Those who have passed : (i) Rs. 100 p.m. after 1 year, of which Rs. 75 shall rank for superannuation benefits.

(ii) Rs. 250 p.m. after 2 years, of which Rs. 200 shall rank for superannuation benefits

Note : If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

(d) AMENDMENT TO REGULATION 21

Regulation 21 shall be substituted by the following :

"21. On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :

- (i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 1650 plus,
- (ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 1650 to 2835 plus,
- (iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 2835 to Rs. 4020 plus,
- (iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4020.

(e) AMENDMENT TO REGULATION 22

Sub Regulation (1), (2) & (3) of Regulation 22 shall be substituted by the following :

"(1) On and from 1-11-1987, where an officer is provided with residential accommodation by the bank, 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him."

"(2) On and from 1-11-1987, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :

Where the place of work is in HRA payable shall be

(i) Major 'A' Class Cities specified 14% of the pay subject as such from time to time in to a maximum of accordance with the guidelines Rs. 375. of the Govt. & Project Area Centres in Group 'A'

(ii) Other places in Area I and 12% of the pay subject Project Area Centres in to a maximum of Group 'B'. Rs. 300.

(iii) Area II and State capitals and 10% of the pay subject capitals of Union Territories not to a maximum of covered by (i) & (ii) above Rs. 250.

(iv) Area III 8% of the pay subject to a maximum of Rs. 225.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, with a maximum of 16% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise."

"(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below :

A

The aggregate of :

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- (ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditions or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation :—

(1) For the purpose of this Regulation "standard rent" means :

- (a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;
- (b) Where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank."

(f) AMENDMENT TO REGULATION 23 :

Sub Regulations (i), (v), (vi), (vii) & (x) of Regulation 23 shall be substituted by the following :—

"(i) On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place, provided that the city compensatory allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmugao, where it was not payable on 1-11-1987 shall be payable with effect from 20-8-1988.

Places	Rates
1	2
(a) Places in Area I and in the State of Goa	6-1/2% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month

"(v) On and from 1-11-1987, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12 per cent of pay maximum Rs. 700 and such other allowance as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6 per cent of his pay maximum Rs. 350.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6 per cent of his pay maximum Rs. 350.

"(vi) On and from 1-11-1987 if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6 per cent of his pay, subject to a maximum of Rs. 250 per month for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be

eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

“(vii) On and from financial year 1989-90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150 for each of the two closings.”

“(x) On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

Place	Rate
1	2
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	5% of pay subject to a maximum of Rs. 130/-
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	6 1/2% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-

Note.—(a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centre with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1-11-1987 and 30-4-1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989, onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.”

(g) AMENDMENT TO REGULATION 24 :

Sub Regulations 1(a) 1(b) (i) & 1(b) (v) of Regulation 24 shall be substituted by the following :—

“(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses.—On and from 1-11-1987, reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100 to Rs. 3060 p.m.	Rs. 600
Rs. 3061 p.m. and above	Rs. 800

Note.—An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

EXPLANATION :

“Family of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.

(v) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members :

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diphtheria, Leprosy, Kidney Ailment.”

(h) AMENDMENT TO REGULATION 25

Regulation 25 shall be substituted by the following :

“(25) On and from 1-11-1987, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a further sum equal to 1-1/2% of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”

(i) AMENDMENT TO REGULATION 34

Sub Regulation (1) of Regulation 34 shall be substituted by the following :

“34(1) On and from 1-4-1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the Bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost.

(j) AMENDMENT TO REGULATION 35

Regulation 35 shall be substituted by the following :

“(35) On and from 1-1-1989, where an officer has put in a service of 24 years he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each of service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave.”

(k) AMENDMENT TO REGULATION 41

Sub Regulations 1(i), (ii), (iii) and (iv) of Regulation 41 shall be substituted by the following :

(41) On and from the date specified by the Board the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :

(i) An officer in Junior Management Grade may travel by 1st class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st class or AC Sleeper by train. He may, however travel by air (economy class) if the dis-

tance to be travelled is more than 500 kms. He may, however, travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by air (economy class).

(iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. However, when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car."

(d) AMENDMENT TO REGULATION 42

Sub Regulation (2)(i) of Regulation 42 shall be substituted by the following :

"42(2)(i) On an from 1-11-1987 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 2100/- p.m. to Rs. 3060/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs 3061/- p.m. and above	Full Wagon	2000 kgs.

(m) AMENDMENT TO REGULATION 45

Sub Regulation (2) of Regulation 45 shall be substituted by the following :

"45(2) The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund, from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10% of 80% of pay on and from 1-11-87 to 31-12-1988, 10% of 90% of pay on and from 1-1-89 to 31-12-1989 and 10% of pay on and from 1-1-1990 of the officer."

(n) AMENDMENT TO REGULATION 46

Sub Regulation (2) of Regulation 46 shall be substituted by the following :

"46(2) The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years.

Note.—If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

KHUSHAL SINGH, Asst. General Manager
(Personnel)

